सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेदवेलु थेवर

बनाम

मद्रास राज्य

(संबंधित अपील के साथ)

(जगन्नाथदास, बी. पी. सिन्हा और पी. बी. गजेन्द्रगडकर जे.)

हत्या-एकल गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि-स्वामित्व-मृत्युदंड, यदि उचित हो तो-विस्तारित करने वाली परिस्थिति-भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 134

अपीलार्थियों पर हत्या का आरोप लगाया गया और गवाह की एकमात्र गवाही पर उन्हें दोषी ठहराया गया। पहले अपीलार्थी को मृत्युदंड और दूसरे को पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया था कि दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि एक मामले मेंः हत्या के आरोप को शामिल करते हुए-अदालत को विवेक के आधार पर, किसी एक गवाह की गवाही पर किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और किसी भी मामले में, कानून का कठोर दंड नहीं देना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह प्रश्न कि क्या ऐसे मामले में अदालत उसे दोषी ठहरा सकती है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और जब तक कि पुष्टि एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है, एक अदालत ऐसे साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकती है, हालांकि

अप्रमाणित, उन मामलों को छोड़कर जहां एकल गवाह की गवाही की प्रकृति स्वयं विवेक के मामले के रूप में आवश्यक है, कि पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए, जैसा कि एक बाल गवाह, एक साथी या एक समान चरित्र के किसी अन्य व्यक्ति के मामले में है।

जहां अदालत ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है, सजा का प्रश्न प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की मात्रा या चरित्र से नहीं, बल्कि किसी भी ऐसी विस्तारित परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना चाहिए जो अपराध की व्यापकता को कम कर सकती हैं।

मोहम्मद सुगुल एसा मामासन रेर अला/आह बनाम द किंग, ए. एल. आर. (1946) पी. सी. 3 और वेमीरेड्डी सत्यनारायण रेड्डी और तीन अन्य बनाम हैदराबाद राज्य, (1956) एस. सी. आर. 247, विशिष्ट।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 1957 की आपराधिक अपील संख्या 24 और 25।
मद्रास उच्च न्यायालय के 1956 के आपराधिक अपील सं. 247 और 248 में 25 जुलाई, 1956 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील और नागापटम में पूर्वी तंजौर प्रभाग के सत्र न्यायालय के 28 मार्च, 1956 निर्णय और आदेश से उत्पन्न 1956 के संदर्भित परीक्षण सं. 41 से विशेष अनुमति द्वारा अपील, 1956 के मामले एस. सी. सं. 5 में।

अपीलार्थियों की ओर से एच. जे. उमरीगर और एस. सुब्रमण्यन।

प्रतिवादी के लिए पी. एस. कैलाशम और टी. एम. सेन।

1957 में 12 अप्रैल न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

सिन्हा. जे.- विशेष अनुमति द्वारा दो अपीलें, जो एक ही घटना से उत्पन्न होती हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के 25 जुलाई, 1956 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जो सत्र न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि करती हैं, पूर्वी तंजौर प्रभाग, नागपट्टिनम में, एस के अधीन। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की आपराधिक अपील संख्या 24,1957 में अपीलार्थी के खिलाफ, कन्नूस्वामी की हत्या और धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश को संशोधित करने के लिए। 302, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 326 आपराधिक अपील संख्या 25,1957 में अपीलार्थी के संबंध में आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय के दौरान, हम 1957 की आपराधिक अपील संख्या 24 में अपीलार्थी को "प्रथम अपीलार्थी" और 1957 की आपराधिक अपील संख्या 25 में अपीलार्थी को "द्वितीय अपीलार्थी" के रूप में बुलाएंगे।

यह घटना, जो दो अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों का विषय थी, 10 नवंबर, 1955 को मुथुपेट में श्रीमती धनबग्यम-अभियोजन गवाह संख्या 1 के पति कन्नूस्वामी की चाय की दुकान के सामने हुई, जिन्हें इस फैसले के दौरान "प्रथम गवाह" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, और अभियोजन पक्ष के लिए प्रमुख गवाह है, क्योंकि, जैसा कि विदित है, अभियोजन पक्ष का मामला और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा पूरी तरह से उनकी गवाही पर निर्भर करती है।

यह घटना एक सिनेमा-घर के निकट हुई, जिसमें कथित निर्मम हत्या के समय दूसरा शो चल रहा था। चूँकि उस समय कन्नूस्वामी द्वारा संचालित चाय की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें चाय की दुकान के पीछे रात के खाने के लिए बुलाया, क्योंकि पति-पत्नी वहां रहते थे। कन्नूस्वामी रात के खाने के लिए शामिल होने वाले थे जब एक बूढा आदमी दुकान में आया और एक कप चाय मांगी। जब कन्नूस्वामी चाय तैयार करने में व्यस्त हो गए, तो दोनों अपीलार्थी परिसर में दौड़ पड़े। बूढा आदमी ग्राहक-स्वाभाविक रूप से भाग गया, और दोनों अभियुक्तों ने कन्नूस्वामी को दुकान से बाहर सड़क के किनारे खींच लिया। और पहले अपीलार्थी ने उसे कई वार दिए-छाती के क्षेत्र में उसके शरीर के सामने के हिस्से में एक अरुवल के साथ- लगभग 2 फीट लंबा एक काटने का उपकरण। कन्नूस्वामी पीठ के बल गिर पड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगे। उसकी पत्नी, जो घर की एकमात्र अन्य सदस्य थी, ने दोनों अभियुक्तों द्वारा उसे छोड़ने के बाद उसका सिर ऊपर उठाकर उसकी गोद में रखने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही, शायद, यह महसूस करते हुए कि पत्नी द्वारा अपदस्थ किए गए पहले प्रहारों के परिणामस्वरूप कन्नूस्वामी की मृत्यु नहीं हुई थी, दोनों आरोपी लौट आए। कन्नूस्वामी की पत्नी, जो हत्या के एकमात्र गवाह के रूप में अदालत में पेश होती है, ने उसका सिर जमीन पर रख दिया और चाय की दुकान की सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। इस बार पहले अपीलार्थी ने कन्नूस्वामी के शरीर को नीचे की ओर लेटा दिया और सिर, गर्दन और पीठ के क्षेत्र में कई घाव दिए। ये चोटें ऐसी थीं जिससे तुरंत मौत हो जाती थी। दूसरे हमले के समय, पहले गवाह, शुनमुगा थेवर-अभियोजन गवाह संख्या 3 के साक्ष्य के अनुसार, सिनेमा घर के मालिकों में से एक आया और आरोपी के साथ विरोध किया, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था। चोट लगने के बाद दोनों आरोपी भाग गए। पहले गवाह

की गवाही के अनुसार, यह पहला अपीलार्थी था, दूसरा अभियुक्त (अभिलेख में ए-2), जिसने अरुवल के साथ काटने की चोटें पहुंचाईं ~ दूसरा अपीलार्थी, पहला अभियुक्त (अभिलेख में ए-1), उस समय पास में खड़ा था जब काटने की चोटें लगी थीं। चाय की दुकान में दो बिजली की बत्तियाँ जल रही थीं, सड़क पर पंचायत बोर्ड की बत्तियाँ जल रही थीं, और सिनेमा-घर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक बत्तियाँ भी जल रही थीं। मृतक की पत्नी ने अपने पति को इस तरह से मृत पाया और गणपति-अभियोजन गवाह संख्या 4 को बताया, जिसकी सड़क के दूसरी तरफ चाय की दुकान थी, और उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने उसे पुलिस स्टेशन में घटना की जानकारी दर्ज कराने के लिए कहा। फिर वह माथुपेट पुलिस स्टेशन गई, लेकिन उसे बंद पाया। वह पुलिस के उप-निरीक्षक के घर गई, जो उसे पुलिस स्टेशन ले गए, और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी. 1) के रूप में उसका बयान दर्ज किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, उप निरीक्षक घटना स्थल पर प्रथम सूचना देने वाले के साथ आए। उन्होंने सुबह-सुबह पूछताछ की।

मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने मृतक व्यक्ति की विधवा (पीडब्लू. 1), गणपति थेवर की चाय की दुकान में सहायक पीडब्लू 2, सिनेमा घर के मालिकों में से एक पीडब्लू 3 और सिनेमा घर के पास एक और चाय की दुकान रखने वाले पीडब्लू 4 गणपति के अलावा अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में पूछताछ की। पी. डब्ल्यू. 2 सिंगाराम ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने वादिवेलु को कन्नूस्वामी और चिन्निया को कुछ फीट दूर वादिवेलु के किनारे खड़े देखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपराध से संबंधित नहीं थे, हालांकि उनके नाम एक ही थे। लोक अभियोजक को इस गवाह से जिरह करने की अनुमति दी गई, जिसने स्वीकार किया कि वह जानता था कि पुलिस कठघरे में

आरोपी की तलाश कर रही थी और उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि ये वे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हत्या की थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि कटघरे में खड़े आरोपी वे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हत्या की थी और यह कि न्यायिक अदालत में उन्होंने पहली बार कहा था कि आरोपी व्यक्ति अपराध से संबंधित नहीं थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय, घटना स्थल पर, चाय की दुकान में और थिएटर में रोशनी जल रही थी। सिनेमा घर के मालिकों में से एक पी. डब्ल्यू. 3 ने अदालत में पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन कहा कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि उसने आरोपी को कन्नूस्वामी पर हमला करते देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि इस गवाह के मुख्य परीक्षण के अभिलेख से ही यह संकेत मिलता है कि लोक अभियोजक ने उससे जिरह की प्रकृति में प्रश्न किए थे, फिर भी पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 के बयानों के अभिलेख के विपरीत यह दर्ज नहीं किया गया है कि इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और लोक अभियोजक को उससे जिरह करने की अनुमति दी गई थी। यह विद्वान सत्र न्यायाधीश की एक पर्ची प्रतीत होती है क्योंकि उनके साथ न्यायिक अदालत में भी ऐसा व्यवहार किया गया था। जाँच उप-निरीक्षक, पी. डब्ल्यू. 14 ने अपनी डायरी के संदर्भ में कहा कि पी. डब्ल्यू. 3 ने उनके सामने कहा था कि उन्होंने आरोपी नंबर 2 को मृतक के सिर और गर्दन को एक अरुवल से काटते हुए देखा था, और आरोपी नंबर 1 को दूसरे आरोपी के बगल में खड़ा देखा था। अभियोजन पक्ष के लिए गवाह संख्या 4-गणपति, जो मृतक कन्नूस्वामी की चाय की दुकान से लगभग 50 से 60 फीट दूर सिनेमा-हाउस के पास एक चाय की दुकान चलाते थे, ने अदालत में कहा कि पहला गवाह उनके पास रोते हुए आया और कहा कि चिन्निया और वादिवेलु थेवर ने उनके पति को

काट दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अदालत में दो आरोपी ये व्यक्ति नहीं थे। इस प्रकार, 2 से 4 तक के अभियोजन पक्ष के गवाहों के पिछले बयान जो भी रहे हों, अदालत में उनका साक्ष्य सीधे अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोषसिद्धि और सजा के आदेश, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित किए गए हैं, केवल पहले गवाह की गवाही पर निर्भर करते हैं।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थियों
की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वे पहली गवाह की एकमात्र गवाही पर निर्भर करते हैं, विशेष रूप से, क्योंकि आगे यह तर्क दिया जाता है कि उसकी गवाही सभी दोषों से मुक्त नहीं है। इस संबंध में अदालत में उनके इस बयान को कि यह दूसरा आरोपी (पहला अपीलकर्ता) था जिसने मृतक कन्नूस्वामी को अरुवल के साथ कटे हुए घावों की संख्या दी थी, प्रतिपरीक्षा में चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान (प्रदर्शनी डी-2) के संदर्भ में उससे जिरह की गई है, और उसने स्पष्ट रूप से कहा हैः
"आरोपी 1 के पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। उन्होंने कोई कट नहीं दिया। मैंने न्यायिक अदालत में यह नहीं कहा है कि आरोपी 1 ने षण्मुघम थेवर द्वारा उसे न काटने के लिए कहने के बाद भी काटना जारी रखा। डी-2 का प्रदर्शन इन शब्दों में हैः
"जब वह काटने के लिए नहीं कह रहा था, तब भी आरोपी 1 काट रहा था। इसके तुरंत बाद आरोपी 1 ने काटना बंद कर दिया और चला गया।

प्रथम गवाह के बयान के संदर्भ में, जैसा कि प्रदर्शनी डी-2 में दर्ज किया गया है, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज

करने की गलती थी। हमने प्रथम गवाह के पूरे साक्ष्य की जांच की है, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया है-जो अभिलेख में मुद्रित नहीं है, लेकिन अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा हमें प्रदान किया गया है- और हमारी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश अपने निष्कर्ष में सही थे कि मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्डिंग इस अर्थ में दोषपूर्ण है कि आरोपी 1 को आरोपी के स्थान पर दर्ज किया गया है, क्योंकि, अपने पूरे बयान के दौरान, प्रथम गवाह ने लगातार कहा था कि यह आरोपी 2 था जिसने वास्तव में अपने पति के खिलाफ घातक हथियार का उपयोग किया था और वह आरोपी 1 केवल उसकी सहायता कर रहा था और उसे बढ़ावा दे रहा था और उसे अपनी उपस्थिति से ताकत दे रहा था। यह कि यह निष्कर्ष अच्छी तरह से स्थापित है, उच्च न्यायालय में अपील के रिकॉर्ड की स्थिति से भी पुष्टि होती है। उच्च न्यायालय में दोनों अपीलार्थियों में से प्रत्येक ने अपने स्वयं के वकील के माध्यम से एक अलग अपील ज्ञापन दायर किया। अपील के किसी भी ज्ञापन में, कोई भी आधार नहीं लिया गया है कि प्रथम गवाह ने न्यायिक अदालत में अपने पिछले बयान के संदर्भ में खुद का खंडन किया था। उनकी गवाही पर केवल 'इच्छुक, कृत्रिम और अप्राकृतिक' के रूप में हमला किया गया था। यह भी सुझाव नहीं दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट (प्रदर्शनी डी-2) द्वारा रिकॉर्डिंग के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था। जब मामले पर उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष बहस की गई, तो फैसले में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि विभिन्न चरणों में पहले गवाह के बयान में इस कथित गंभीर विसंगति का कोई बिंदु बनाया गया था। उच्च न्यायालय में, यह तर्क देने की मांग की गई थी कि वह एक इच्छुक गवाह थी, हालांकि उसकी गवाही पूरी तरह से सुसंगत थी, जैसा कि उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से दिखाई देगा।

"यह साबित करने के लिए कि यह दो आरोपी थे जिन्होंने मृतक को ये चोटें पहुंचाईं, अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया। इन चार गवाहों पर, पी. डब्ल्यू. एस. 2, 3 और 4 दोनों समादेशित न्यायालय और सत्र न्यायालय में पक्षद्रोही हो गए। एकमात्र गवाह जो पूरे समय कायम रहा वह पी. डब्ल्यू. 1 था जो मृतक की पत्नी के अलावा और कोई नहीं है।"

उच्च न्यायालय में दायर इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए याचिका के संदर्भ में भी यही स्थिति थी। यह दोनों अपीलार्थियों की ओर से एक संयुक्त याचिका थी, और 13 आधार लिए गए थे। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि पहले गवाह की गवाही को ऐसी किसी विसंगति से दूषित किया गया था जैसा कि इस न्यायालय में करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के बाद पहली बार, इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में, यह आधार लिया गया है कि उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि प्रथम गवाह की गवाही इस कारण से अविश्वसनीय थी कि न्यायिक अदालत और सत्र न्यायालय में उसके बयान के बीच कथित विसंगति थी। इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि प्रथम गवाह के साक्ष्य को अभिलिखित करने में गलती के बारे में विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष को, समादेशित अदालत द्वारा, नीचे दिए गए न्यायालय में किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है।

पहले गवाह की सच्चाई के खिलाफ हमले का दूसरा आधार यह है कि उसने कहा था कि षण्मुघम थेवर-अभियोजन गवाह संख्या 3 ने भी पहले अपीलकर्ता को अपने पति को घातक प्रहार करते देखा था, और पी.

डब्ल्यू. 3 के विरोध के बावजूद हमलावर ने अपने प्रहार जारी रखे। यह तर्क इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि अभियोजन गवाह संख्या 3 सच कह रहा है और इसलिए, उसका साक्ष्य प्रभावी रूप से पहले गवाह के साक्ष्य के विपरीत है। पी. डब्ल्यू. 3, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोक अभियोजक द्वारा जाँच अधिकारी (पी. डब्ल्यू. 14) के समक्ष अपने पिछले बयान के संदर्भ में प्रतिपरीक्षा की गई थी। पी. डब्ल्यू. 14 ने कहा है कि उनके समक्ष पी. डब्ल्यू. 3 ने अदालत में जो कहा था, उसके ठीक विपरीत कहा था। प्रारंभिक चरण में, पुलिस के समक्ष और बाद में जब अदालत में जाँच की जाती है, तो पीडब्लू 3 का बयान गलत हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही सच नहीं हो सकते। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत में पी. डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य सही था। अदालत में उसका साक्ष्य इस आधार पर पहले गवाह के साक्ष्य को मिटाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है कि यह पी. डब्ल्यू. के विपरीत है 3 ने कहा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस तर्क के समर्थन में आग्रह किए गए आधारों में से कोई भी आधार नहीं है कि पहले गवाह का साक्ष्य अविश्वसनीय है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण गवाह होने के नाते, पहली गवाह को उससे जिरह में गंभीर परीक्षण के लिए रखा गया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, जो उसके मृत पति के पिछले जीवन पर एक बहुत ही अस्पष्ट प्रकाश डालता है। उसने स्वीकार किया कि उसे हत्या करने के लिए जीवन भर के लिए ले जाया गया था और उसकी रिहाई के बाद भी, उसे दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए दो बार जेल भेजा गया था। यदि पहली गवाह झूठ बोलने या कम से कम अपने पति के अतीत को छिपाने के लिए इच्छुक थी, तो वह विफल स्मृति या जानकारी की कमी के पीछे शरण ले सकती थी, जो कि गवाहों को धोखा देने की एक असामान्य विशेषता नहीं है। उसके साक्ष्य, समग्र

रूप से पढ़े जाने पर, काफी सही लगते हैं, और हमें उस पर कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं है। यह सच है कि अदालत में उसके साक्ष्य का पी. डब्ल्यू. के साक्ष्य द्वारा खंडन करने की मांग की गई है 2 से 4, लेकिन गवाहों के बाद के समूह को विश्वसनीय नहीं दिखाया गया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने स्वयं के कारणों से विभिन्न चरणों में अलग-अलग बयान दिए हैं। उनकी गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और इसलिए हम पी. डब्ल्यू. एस. की गवाही की तुलना में पहले गवाह की गवाही को दरकिनार नहीं कर सकते हैं 2 से 4। प्रथम गवाह की गवाही घटना के एक घंटे से भी कम समय के भीतर बिना किसी टालने योग्य देरी के पुलिस स्टेशन में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही गई बातों के अनुरूप है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत में उसका बयान, एक विचार के बाद, या अन्य इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पढ़ाए जाने का परिणाम है। दोहरे हमले की उसकी कहानी, पहले सामने और बाद में पीड़ित के पीछे और तरफ, मेडिकल ऑफिसर- P.W. 8 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। मृतक व्यक्ति पर दर्जन भर घावों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक नहीं है जो सभी विद्वान सत्र न्यायाधीश के फैसले में विस्तार से बताए गए हैं जिन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक और संतोषजनक निर्णय लिखा है।

वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि एकल गवाह की गवाही पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है, भले ही वह झूठी गवाह साबित नहीं हुई हो। अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह दावा भी नहीं किया गया है कि यह कानून का नियम है। उन्होंने इसे केवल विवेक के आधार पर रखा है कि, आम तौर पर, अदालत को हत्या के आरोप से जुड़े मामले में, एक गवाह की गवाही पर एक आरोपी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस संबंध में हमारा

ध्यान मोहम्मद सुताल ईसा मामासन रेर अल्लाह बनाम राजा (1) के मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के उनके प्रभुत्वों की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया था। उस मामले में, उनके लॉर्डशिप्स ने हत्या के मामले में एक गवाह की गवाही की पुष्टि की। यह सच है कि उस मामले में अदालत को हत्या के आरोप के समर्थन में एकल गवाह की गवाही की खोज करनी पड़ी और पुष्टि करनी पड़ी, लेकिन उस गवाह की गवाही दो कमियों से ग्रस्त थी। अर्थात्ः

(I) घटना के समय गवाह लगभग 10 या 11 वर्ष की लड़की थी।

(2) लड़की गवाह को शपथ नहीं दिलाई गई थी क्योंकि अदालत ने यह नहीं माना था कि वह शपथ की प्रकृति को समझने में सक्षम थी, हालांकि वह गवाही देने में सक्षम थी।

यह सोमालीलैंड का एक मामला था जिसमें भारतीय शपथ अधिनियम (1872 का 1) और भारतीय शपथ अधिनियम (1873 का 10) के प्रावधान लागू किए गए थे। महामहिम परिषद में अपील करने के लिए इस आधार पर विशेष अनुमति दी गई थी कि स्थानीय अदालतों ने 10 या 11 साल की उम्र की लड़की के अप्रमाणित साक्ष्य को स्वीकार किया था और उस पर कार्रवाई की थी। उनके अधिपतियों ने दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि सबूत, जैसे कि यह था, स्वीकार्य था। अपने निर्णय के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं (पीपी पर। 5-6) जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक हैंः

"अपीलार्थी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह मानते हुए कि अप्रमाणित साक्ष्य स्वीकार्य था, न्यायालय उस पर तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की गई हो। इंग्लैंड में जहां एक बच्चे से अप्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है, यह हमेशा प्रदान किया गया है कि साक्ष्य की पुष्टि किसी विशेष सामग्री में की जानी चाहिए जो अभियुक्त को निहित

करती है। लेकिन भारतीय अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सबूत को स्वीकार्य बनाया जाता है, चाहे इसकी पुष्टि हो या नहीं। एक बार जब स्वीकार्य साक्ष्य हो जाता है तो एक अदालत उस पर कार्रवाई कर सकती है; जब तक कि क़ानून द्वारा आवश्यक न हो, पुष्टि केवल साक्ष्य की महत्ता पर जाती है। व्यवहार में यह एक ठोस नियम है कि किसी बच्चे के अप्रमाणित साक्ष्य पर कार्य नहीं किया जाए, चाहे वह शपथ हो या शपथ न हो, लेकिन यह विवेक का नियम है न कि कानून का।

वेमीरेड्डी सत्यनारायण रेड्डी और तीन अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (1) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी इस तर्क के समर्थन में भरोसा किया गया था कि एक हत्या के मामले में अदालत एक ही गवाह की गवाही की पुष्टि करने पर जोर देती है। इस न्यायालय के उक्त सूचित निर्णय में पी. डब्ल्यू. 14 को "गोपाई नामक एक धोबी लड़के" के रूप में वर्णित किया गया है। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने हत्या देखी थी और उसकी गवाही पर इस आधार पर हमला किया गया था कि वह एक सहयोगी था। हालाँकि इस अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह एक सहयोगी था, लेकिन यह माना गया कि उसकी स्थिति एक सहयोगी के समान थी। इस न्यायालय ने एकल गवाह की गवाही की पुष्टि करने पर इस आधार पर जोर नहीं दिया कि एकमात्र सबूत था जिसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती थी, बल्कि इस आधार पर कि हालांकि वह एक सहयोगी नहीं था, लेकिन उसका सबूत उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक सहयोगी के समान था, जैसा कि पृष्ठ 252 पर निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होगाः

"हालांकि वह एक सहयोगी नहीं था, फिर भी हम इस विशेष मामले में भौतिक विवरणों पर पुष्टि चाहते हैं, क्योंकि वह अपराध का एकमात्र गवाह है और क्योंकि चार लोगों को अपनी एकमात्र गवाही पर फांसी देना असुरक्षित होगा जब तक कि हम आश्वस्त न हों कि वह सच बोल रहा है। हालाँकि, इस तरह की पुष्टि अपराध के वास्तविक अपराध के सवाल पर होने की आवश्यकता नहीं है; यदि यह आवश्यकता थी, तो हमारे पास स्वतंत्र गवाही होगी जिस पर कार्रवाई की जाए और उस व्यक्ति के साक्ष्य पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी स्थिति, इस विशेष मामले में, किसी सहयोगी के समान हो सकती है, हालांकि बिल्कुल वैसी नहीं है।"

भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य फैसलों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक नहीं है, जिसमें अदालत ने कानून के प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि उन मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए एक ही गवाह की गवाही की पुष्टि करने पर जोर दिया था। संबंधित अधिकारियों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को सुरक्षित रूप से दृढ़ता से स्थापित किया जा सकता हैः

(1) एक सामान्य नियम के रूप में, एक अदालत एकल गवाह की गवाही पर कार्रवाई कर सकती है हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एक विश्वसनीय गवाह उदासीन चरित्र के कई अन्य गवाहों की गवाही से अधिक महत्वपूर्ण है।

(2) जब तक कानून द्वारा पुष्टि पर जोर नहीं दिया जाता है, तब तक अदालतों को पुष्टि पर जोर नहीं देना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां एकल गवाह की गवाही की प्रकृति स्वयं विवेक के नियम के रूप में

आवश्यक है, कि पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए एक बाल गवाह के मामले में, या एक गवाह जिसका सबूत एक साथी या एक समान चरित्र का है।

(3) एकल गवाह की गवाही की पुष्टि आवश्यक है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए और इस तरह के मामले में कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और बहुत कुछ उस न्यायाधीश के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है जिसके समक्ष मामला आता है।

इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि एक हत्या के मामले में, अदालत को गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, बहुत व्यापक रूप से कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि "किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी भी मामले में गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।" विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा। इंग्लैंड में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, सरकार के साक्ष्य के कानून-9वें संस्करण में कई क़ानून बनाए गए हैं। 1100 और 1101 एकल गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि को मना करते हैं। भारतीय विधानमंडल ने ऊपर उद्धृत धारा 134 में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के लिए ऐसे किसी भी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है। इस खंड में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कहावत है कि "साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना

चाहिए"। हमारे विधानमंडल ने इस तथ्य को वैधानिक मान्यता दी है कि यदि एक विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया जाता है तो न्याय के प्रशासन में बाधा आ सकती है। ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई अपराध केवल एक गवाह की उपस्थिति में किया गया हो, उन मामलों को छोड़कर जो असामान्य घटना के नहीं हैं, जहां अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि विधानमंडल गवाहों की बहुलता पर जोर देता है, तो ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। यही वह जगह है जहाँ पीठासीन न्यायाधीश का विवेक कार्य में आता है। इस प्रकार मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना है। यदि अदालत द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। जिस प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति का अपराध एक गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है, उसी प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति की बेगुनाही एक गवाह की गवाही से स्थापित की जा सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए काफी संख्या में गवाह सामने आ सकते हैं। इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्ः

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकता है या बरी कर सकता है, अगर यह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाया जाता है। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को समान रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों की पुष्टि करनी होती है। गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक और खतरा है। एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों के अधीनता को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध हो। स्वाभाविक रूप से न्यायालय को ऐसी गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है और उन सभी कलंकों से मुक्त है जो मौखिक गवाही को संदेह के लिए खुला रखते हैं, तो ऐसी गवाही पर कार्रवाई करना उसका कर्तव्य बन जाता है। कानूनी रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां अदालत को अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक गवाह की गवाही पर निर्भर रहना पड़ता था और उस पर कार्रवाई करनी पड़ती थी। इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन अपराधों या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपनी प्रकृति से, संदिग्ध है, जो अपराध में एक प्रतिभागी है। लेकिन; जहां ऐसे कोई असाधारण कारण काम नहीं कर रहे हैं, यह अदालत का

कर्तव्य बन जाता है कि वह दोषी ठहराए, अगर यह संतुष्ट हो कि एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसलिए, हमारे पास पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है।

अंत में, यह आग्रह किया गया कि यह मानते हुए कि अदालत पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने और पहले अपीलार्थी के खिलाफ हत्या के लिए दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए इच्छुक थी, अदालत को कानून का अत्यधिक दंड नहीं देना चाहिए और रिकॉर्ड की स्थिति में, कानून द्वारा प्रदान की गई कम सजा को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने वाला माना जाना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं- पहला सवाल जिस पर अदालत को इस तरह के मामले में विचार करना है, वह यह है कि क्या आरोपी को अदालत की संतुष्टि के अनुसार अपराध करने के लिए साबित किया गया है। यदि अदालत अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई के बारे में आश्वस्त है, तो दोषसिद्धि का पालन करना होगा। सजा के प्रश्न का निर्धारण अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की मात्रा या चरित्र के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस तथ्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या कोई ऐसी विस्तारित परिस्थितियाँ हैं जो अपराध की व्यापकता को कम करने के लिए कही जा सकती हैं। यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि ऐसी कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं, तो ही कानून द्वारा प्रदान की गई दो सजाओं में से छोटी सजा देना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, सबूत की प्रकृति का सजा की प्रकृति से कोई लेना-देना नहीं है। सबूत की प्रकृति केवल दोषसिद्धि के सवाल पर निर्भर कर सकती है- चाहे आरोपी दोषी साबित हुआ हो या नहीं। यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि दोषी को अभियुक्त के घर लाया गया है, और दोषसिद्धि के

बाद, सबूत की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। सवाल यह है कि क्या सजा दी जानी चाहिए, यह अदालत को किसी भी विस्तारित परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में मामले की सभी परिस्थितियों में तय करना है। लेकिन सबूत की प्रकृति, जैसा कि हमने संकेत दिया है, का सजा के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले में, ऐसी कोई विस्तारक परिस्थितियाँ नहीं हैं जिन पर इस दृष्टिकोण के समर्थन में वैध रूप से आग्रह किया जा सके कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कम दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह एक निर्मम हत्या थी। आरोपी दूसरी बार आए, यह देखने के लिए दृढ़ थे कि उनका पीड़ित संभवतः हत्यारों के हाथों से न बचे।

जहाँ तक दूसरे अपीलार्थी का संबंध है, हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि से बचने के लिए भाग्यशाली था, जिसकी गहन जांच नहीं हो सकती है। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा का हकदार है।

उपरोक्त कारणों से, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।